



## The Noida International University, Uttar Pradesh Act, 2010

Act 27 of 2010

### Keyword(s):

Faculty, Institution, College, Registrar, Trust, Prescribed, University, Hostel

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग- 1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2010  
आश्विन 20, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1108/79-वि-1-10-1(क)23-10  
लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2010.

अधिसूचना  
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 27 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

मार्कति एजुकेशनल ट्रस्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकराठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. यह अधिनियम, नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

2 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

- (क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है।
- (ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है।
- (ग) "कुलाधिपति", "प्रतिकुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है।
- (घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है।
- (ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केंद्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है।
- (च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी है।
- (छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य शामिल हैं।
- (ज) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की "कार्य परिषद्" से है।
- (झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है।
- (अ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है।
- (ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है।
- (ठ) "संस्था" "महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो।
- (ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है।
- (ढ) "अभिलेखों और प्रकाशन" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है।
- (ण) "परिनियमों और अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है।
- (त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है।
- (थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाये और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदामिहित किया जाय।
- (द) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है।
- (ध) "ट्रस्ट" का तात्पर्य भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के अधीन पंजीकृत गारुति एजुकेशनल ट्रस्ट, रघुनाथ सदन, गोपालगंज, सराय लावरिया जिला अलीगढ़ से है।

(ii) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-3 के अधीन स्थापित नोयडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से है।

3-(1) गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा नोयडा इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

4 ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :- विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुयी भूमि का समुचित स्वामित्व हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पाँच करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण की प्रतिष्ठापना।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना।

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का तनाया जाना।

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जान की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

5 (1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा। विश्वविद्यालय का आरम्भ

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तों पूरी कर ली गई हैं, संबंधित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

6-विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिये आवश्यक वातावरण और सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा :- विश्वविद्यालय का उद्देश्य

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और जानार्जन जिसमें ऑनलाईन जानार्जन, मिश्रित जानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसी अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें।

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन

(ग) अन्तर्शांखीय अध्ययन

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

7 विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना। विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

(ख) विज्ञान, अभियंत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मसी, प्रबंधन, होटल, एवम् रातकार प्रबंधन; विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन आदि ज्ञान इत्यादि विषयों की परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और परिसर केन्द्रों या केंद्रों से दूरस्थ प्रवेश अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रसिद्धि करना ।

(मा) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात व्यक्तियों को प्रोफेसर (मिनिस्ट्र) के अंतर्करण से नियुक्त करना ।

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, परीक्षाओं की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणालि के आधार पर प्रमाणित या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त व्यवस्था से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लेना ।

(ङ) विहित रीति से मानक उपाधियों या अन्य शैक्षणिकताएं प्रदान करना ।

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण तथा संशोधन प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हों ।

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, उपाचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियों करना ।

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का रूजान करना तथा उन पर नियुक्तियों करना ।

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उच्चतर ज्ञान हो को स्थायी रूप से या किसी निमित्तित अदिति के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना ।

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश का प्राधिकरण या संस्था से ऐसी शैति से और ऐसी प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना ।

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केंद्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुसंधान करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य का अग्रसार करने के लिये आवश्यक हो ।

(ठ) अध्ययतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, शिक्षावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ।

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रों की स्थापना, अनुसंधान तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण, कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिये प्रासाहित करना ।

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार संकाय के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित जाना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ।

(ण) परिचियों के अनुसार यथार्थिथि केंद्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की स्थापना करना ।

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई प्रणालि हो सकती है ।

- (थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;
- (द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे.
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय.
- (न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बन्धन के लिये व्यवस्था करना.
- (प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना.
- (फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना या आडगानकृत करना.
- (ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें.
- (भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना.
- (ग) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के समी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों।

8-(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये प्रवेश और मानक जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

9- विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहाँ से स्नातक करने के लिये हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा।

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण संगठन-समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

10 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे -

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (क) कुलाधिपति,  
(ख) प्रति कुलाधिपति;

- (ग) कुलपति
- (घ) प्रति कुलपति
- (ङ) निदेशक/प्रधान
- (च) कुलसचिव
- (छ) परीक्षा नियंत्रक
- (ज) छात्र कल्याण का संकायध्यक्ष
- (झ) संकायों के संकायध्यक्ष
- (ञ) मुख्य कुलानुशासक
- (ट) कोषाध्यक्ष
- (ठ) वित्त अधिकारी, और
- (ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11--(1) ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रति-कुलाधिपति

12--(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13--(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाये।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सगस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

14 (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय। प्रतिकुलपति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करना।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

15-निदेशक या प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित की जाए। प्राचार्य या निदेशक

16-(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए। कुलसचिव

(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद और विद्यापरिषद का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

17-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय। संकायाध्यक्ष

18-कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए। कोषाध्यक्ष

19- (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

20- छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें। अन्य अधिकारी

21-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) सभा

(ख) कार्य परिषद

(ग) विद्या परिषद

(घ) वित्त समिति

(ङ) नियोजन बोर्ड

(च) पाठ्य बोर्ड

(छ) संकाय बोर्ड

(ज) परीक्षा समिति

(झ) प्रवेश समिति और

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।



सभा	22--(1) सभा का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।
	(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, यथा :-
	(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिये अद्युपायों का सुझाव देना ;
	(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;
	(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा निजी निकायों के लिये, जहां यथा विहित अवधि के लिये विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना ;
	(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जैसा विहित किया जाय।
कार्य परिषद	23--(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।
	(2) कार्य परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।
विद्या परिषद	24--(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिषदों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।
	(2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।
वित्त समिति	25--(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।
	(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।
नियोजन बोर्ड	26--(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अयस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करे।
	(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाये।
संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी	27--संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिषदों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जायें।
परिषदों का प्रयोजन की शक्ति	28--(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिषदों बनाएगी।
	(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषदों निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :-
	(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;
	(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की शक्तियाँ का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलक्षियों ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलक्षियों ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिये दायित्व लेने के लिये एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं,

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारेकी प्रक्रिया

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषदके समक्ष अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना ;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हैं।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिये विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्य परिषद द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

29- इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेश कार्य अध्यादेश बनाने की परिषद द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये शक्ति उपबन्ध किये जा सकेंगे अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना ;
- (ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;
- (घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;
- (ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिये प्रभाय शुल्क का निर्धारण ;
- (च) अधिछात्रपत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें ;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसूचीकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है ;
- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (झ) छात्रों के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हो, और उनके लिये विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना ;
- (ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से गिन कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ ;
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;
- (ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत् निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति ;
- (ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य ;
- (ढ) परीक्षकों, अनुसूचीकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले परिश्रमिक ;
- (ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्ध और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों ;

वार्षिक रिपोर्ट

30-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउंटेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्यपरिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

32--(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिणियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/ काम पर लगाया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यथित कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति को विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

33--(1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थित, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नागांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपात्तरित या फलट सकता है।

अपील करने का अधिकार

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

34-- विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाए।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

35-- यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36-- जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिणियमों के अधीन समितियों नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे होंगे।

समितियों का गठन

37-- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से गिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिन्हें स्थान रिक्त हुये हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिये जिसका प्रावधान उपर्युक्त धारा में किया गया हो, यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

रिक्तियों का भरा जाना

38-- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

विश्वविद्यालय के  
अभिलेखों को  
प्रमाणित करने की  
शक्ति

39- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना कार्यवाही, रांकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, रांकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और  
अध्यादेशों का  
प्रकाशन

40-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास  
निधि

41-(1) ट्रस्ट का से कम दस करोड़ रु० की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थाई विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42-(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया तो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालयों के सभी आवश्यक धर्मों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

43-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुसूचना

44 धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुये ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

- 45-विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और वित्तीय शर्तें नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।
- 46-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क परिनियम एवम् अध्यादेश के शुल्क कम में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।
- 47-(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय। सूचनाओं और अभिलेखों की मांग करने के लिये राज्य सरकार की शक्तियां
- (2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशोंके उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा-51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।
- 48-(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा। विश्वविद्यालय का विघटन
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।
- 49-(1) धारा-48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा। विश्वविद्यालय का व्यय
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।
- 50-(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुये विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो छः मास से कम नहीं होगा कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना
- (2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।
- (4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात् -
- (क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दें।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

विघटन / मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियां / उत्तरदायित्व की प्राप्ति

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

51-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

52-अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से सम्बन्धित हो जायेंगे।

53-(1) राज्य सरकार ऐसी कितनी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वह परिष्कार परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे :-

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट, अलीगढ़, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या, 2 सन् 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय जिससे कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पाठ्यक्रमों की समुचित संशुद्धि, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधा प्रदान की जा सके।

तदनुसार नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
के०के० शर्मा,  
प्रमुख सचिव।

No. 1108(2)/LXXIX-V-1-10-1(ka)23-10

Dated Lucknow, October 12, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Noida International University Uttar Pradesh Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya-27 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 09, 2010 :—

**THE NOIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH,  
ACT, 2010**

(U.P. Act no. 27 of 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

*to establish and incorporate a teaching University sponsored by Maruti Educational Trust, Aligarh, Uttar Pradesh and to provide for matters connected there with or incidental thereto*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Noida International University, Uttar Pradesh Act, 2010. Short title



## Definition

1. In this Act, unless the context otherwise requires,-
- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
  - (b) "Board" means the Board of Studies or the Planning Board, or any other Board of the University;
  - (c) "Chancellor", "Pro-Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" mean respectively the Chancellor, the "Pro-Chancellor" the Vice-Chancellor the Pro-Vice-Chancellor of the University;
  - (d) "Court" means the Court of the University;
  - (e) "Director/Principal" means the Head of an Institution, a College, a Centre and a School, or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;
  - (f) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies and Research.
  - (g) "Employee" means any person appointed by the University, and includes a teacher or any other member of the staff of the University;
  - (h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
  - (i) "Existing College" means a college or an institution which imparts professional education and is proposed to be merged, run and maintained by the University;
  - (j) "Faculty" means a Faculty of the University;
  - (k) "Hostel" means Scholar/Students Hostel of the University;
  - (l) "Institution/College" means a college including existing college or an Institution established or maintained by or associated or constituent to the University in accordance with this Act and the Statutes.
  - (m) "Prescribed" means prescribed by Statutes;
  - (n) "Records and Publication" means the Records and Publication of the University;
  - (o) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and the Ordinance of the University for the time being in force;
  - (p) "Student" means a student enrolled in the register of the University;
  - (q) "Teacher of the University" means Professors, Associate Professors, Readers, Assistant Professor, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting education/instructions of conducting research in the University and are designated as Teachers by the Ordinances;
  - (r) "Treasurer", "Registrar", "Deputy Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian" or "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Deputy Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examination, the Librarian or the Proctor of the University;
  - (s) "Trust" means Maruti Educational Trust, Raghunath sadan, Gopalgang sarai lavaria in district Aligarh registered under the Indian Trusts Act, 1882;
  - (t) "University" means the Noida International University, Uttar Pradesh established under section 3.

3. (1) There shall be established at Gautam Buddha Nagar in Uttar Pradesh a University by the Trust in the name of the Noida International University Uttar Pradesh.

Establishment of the University.

(2) The University shall be a body corporate.

4. The sponsoring body, the Trust shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely :-

Conditions for the establishment of the University

- (a) duly possesses minimum 50 acres contiguous land earmarked for the University;
- (b) Construct on land referred to in clause (a) buildings of at least 24000 sq. metre carpet area, out of which at least 50 percent shall be for academic and administrative purposes.
- (c) Install equipments in offices and laboratories worth minimum Rs. Five crore in the building referred to in clause (b)
- (d) appoint teachers and establish infrastructure of the department/ school for the purposes of teaching and/or research in at least seven subjects as per standards laid down by the University Grants Commission;
- (e) make the Statutes and the Ordinance for the administration and functioning of the University;
- (f) such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

5. (1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Trust a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.

Starting of the University

(2) The State Government shall issue the letter of authorization after receipt of an unambiguous affidavit along with documents from the Trust to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

6. The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and skill by providing instructional, research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:-

Objects of the University

- (a) innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training and learning including on-line learning, blended learning continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;
- (b) studies in various disciplines;
- (c) inter disciplinary studies;
- (d) national intimation, secularism, social equity and engineering of international understanding and ethics.

7. The University shall have the following powers, namely:-

Powers of University

- (a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(b) to impart and promote the study of science, engineering and technology, Bio and Medical Sciences, Dental Science, Pharmacy, Management, Hotel and Hospitality Management, Law and other Professional courses and also History, Culture, Commerce, Economics, Humanities, Philosophy, Art etc. through in-campus off-campus offshore-campus and satellite centres or by conducting centres or by distant educational programmes etc.

(c) to honor educational stalwarts and persons of academic eminence with the decoration of professor Emeritus.

(d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause:

(e) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed:

(f) to provide education and training including correspondence and such other courses, to such persons who are not members of the University, as it may determine:

(g) to institute Directorships Principalships, Professorships, Associate Professorships, Readership, Assistant Professorships, Lectureships and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same:

(h) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto:

(i) to appoint/engage persons of eminence working in any other University or Organization permanently or for a specified period:

(j) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in India and abroad in such manner and for such purpose as the University may determine:

(k) to establish and maintain schools, centres, specialized laboratories or other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects:

(l) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes:

(m) to establish and maintain and supervise residences, hostels within the University and promote the health and general welfare activities for students and staff:

(n) to make provisions for research and consultancy; and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary:

(o) to declare centre, an institution, a department, or school, as the case may be, in accordance with the Statutes:

(p) to determine standards for admission into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing:

(q) to demand and receive payment of fees and other charges:

(r) to make special arrangement in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;

(s) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University.

(t) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;

(u) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable for the welfare of the University;

(v) to borrow, mortgage or hypothecate with the approval of the Trust on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;

(w) to appoint either on contract or otherwise, visiting professors, emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University.

(x) to organize and to undertake extra-mural studies and extension service;

(y) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

8. (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws for the time being in force.

Admission and Standards

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and other statutory bodies as the case may be;

(3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and specific council.

9. The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat;

University open to all classes and creeds

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens shall be regulated by the order of the State Government issued from time to time.

10. The following shall be the officers of the University:-

Officers of the University

- (a) the Chancellor;
- (b) the Pro-Chancellor;
- (c) the Vice-Chancellor;
- (d) the Pro-Vice-Chancellor;
- (e) Director/Principal
- (f) the Registrar;

(g) the Controller of Examinations;

(h) the Dean of Students Welfare;

(i) the Dean of Faculty;

(j) the Chief Proctor;

(k) the Treasurer;

(l) the Finance Officer; and

(m) such other officers as may be declared by the Statute to be officers of the University;

The Chancellor

11. (1) The Chancellor shall be appointed by the Trust for a period of three years.

(2) The Chancellor shall by virtue of his office, be the Head of the University and shall constitute interim Executive Council.

(3) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the Trust resign his office.

The Pro-Chancellor

12. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Trust for a period of three years.

(2) The Pro-Chancellor shall assist the Chancellor in discharging his duties and preside at the convocation in his absence.

(3) The Pro-Chancellor may in writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office.

The Vice-Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed, for a period of three years.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Academic Council and Planning Board of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University;

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters;

Provided that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of communication of such decision. The Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

The Pro-Vice-Chancellor

14. (1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Pro-vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Trust.

15. The Director/Principal shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Director /  
Principal

16. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.

The Registrar

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other function as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

17. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Dean of Faculty

18. The Treasurer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such function as may be prescribed.

The Treasurer

19. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Finance Officer

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee.

(20) Manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University including the Dean of Students Welfare, Controller of Examination and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

Other Officers

21. The following shall be the authorities of the University :-

Authorities of the  
University

(a) the Court;

(b) the Executive Council;

(c) the Academic Council;

(d) the Finance Committee;

(e) the Planning Board;

(f) the Board of Faculties;

(g) the Admissions Committee;

(h) the Examination Committee, and

(i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

22. (1) The Constitution of the Court and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

The Court

(2) Subject to the provisions of this Act the Court shall have the following power and functions, namely:-

(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University;

(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and Annual Accounts of the University and Audit Report of such accounts;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;

(d) to perform such other functions as may be prescribed

The Executive Council

23. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University

(2) The Constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

The Academic Council

24. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The Constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Finance Committee

25. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the finance matters.

(2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.

The Planning Board

26. (1) The Planning Board shall be the Principal Planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission or the respective Councils.

(2) The constitution, of the planning Board, term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

Board of Faculty, Admission Committee, Examination Committee and other Authorities of the University.

27. The constitution powers and functions of the Boards of faculties the Admission Committee, the Examination Committee and of such other authorities of the University which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Power to make statutes

28. (1) The Executive Council shall make the statutes for carrying out purposes of this Act.

(2) Subject to the provisions of this Act the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:

(a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff and their emoluments;

(e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the University or Institution for specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;

(g) the principals governing seniority of service of employees;

(h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University;

(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or students against the action of any officer or other authority of the University;

(j) the conferment of honorary degrees;

(k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinction;

(l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) the maintenance of discipline among the students;

(n) the establishment and abolition of Department, Centers and other constituted institutions/Colleges etc;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(p) all other matters, which may by this Act are to be or may be prescribed.

(3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor may direct the University to make provisions in the Statutes, in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit.

29. Subject to the provision of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Executive Council which may provide for all or any of the following matters, namely

Power to make Ordinances

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examination;

(d) the award of degree, diploma, certificate and other academic distinction, the qualification for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same.

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;



(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of Centre of Studies, Boards of Studies, interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or association;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic mileage of the University;

(n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

Annual Report

30. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed and the Court shall consider the report in its annual meeting.

(2) The Court shall submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.

Annual Accounts

31. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute.

(2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of the Executive Council.

Condition of service of employees

32. (1) Every employee of the University shall be appointed / engaged as per provisions of the Statutes.

(2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Executive Council who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months from the date of its reference.

(3) The aggrieved employee may file an appeal against the order of the Executive Council to the Chancellor.

(4) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on ad-hoc or part time or casual basis shall be heard and decided finally by the head of the concerned department.

(5) Any person aggrieved by the order of the Vice-Chancellor may prefer an appeal to the Chancellor. The decision of the Chancellor in such an appeal shall be final and no suit shall lie in any court in respect of the matters decided by the Chancellor.

33. (1) Any student or candidate for an examination, whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council, Proctorial Board or Controller of Examinations as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such order or copy of such resolution by him in writing appeal to the Vice-Chancellor to reverse the decision of the aforesaid authorities or the concerned Committee, as the case may be.

Right to Appeal

(2) Any decision taken by the Vice-Chancellor shall be Final.

34. The University may constitute for the benefit of its employees such pension or welfare schemes or provident fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be decided by the Executive Council.

Employees provident fund and pensions

35. If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Disputes as to the constitution of Authorities and bodies

36. Where any authority of the University is given power under this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees shall as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case may think fit.

Constitution of Committee

37. All vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled as soon as may be convenient by the person or body who appointed, nominated or co-opted the members whose place has become vacant for the remaining term for which he has been appointed or co opted.

Filling of the Vacancies

38. No act or proceedings of any authority of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Invalidity of Proceeding

39. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima-facie evidence of the such receipt, applications, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein where the original would, if produced have been admissible in evidence.

Mode of proof of University records

40. (1) Every Statute or Ordinance made under this Act shall be made available in writing.

Publication of statutes and ordinances

(2) Each new Statute or Ordinances made under this Act shall be enforced as soon as it is made by the competent authority.

41. (1) The Trust shall establish a permanent endowment fund of at least rupees ten crore.

Permanent Endowment fund

(2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

General Fund

42. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:

(a) all fees which may be charged by the University;

(b) all sums received from any other source;

(c) all contributions made by the Trust and

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

Development Fund

43. (1) The University shall also establish development fund to which the following money shall be credited, namely:

(a) development fees, which may be charged from students;

(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;

(c) all contributions made by the Trust;

(d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force; and

(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) the money credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University

Maintenance of Fund

44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall subject to general supervision and control of the Court be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

Financial Condition

45. The University shall not be eligible for any grant in aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.

Fees

46. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with laws for the time being in force.

Power of State Government to call for information and records

47. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finance and other affairs of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the Act or the Statutes or Ordinances made hereunder may issue such directions to the University under section 51 as it may deem necessary.

Dissolution of University

48. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitutions or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.

(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangement for administration of the University from the date of dissolution of the university and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses or studies in such manner as may be prescribed.

49. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under section 48 shall be met out of the permanent endowment, the general fund, and the development fund.

Expenditure of the University during dissolution

(2) If the funds referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the university by the State Government.

50. (1) Where the State Government receives a complaint that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act, it shall require the University to show cause within such time, which shall not be less than two months referring a copy of the complaint as to why the University should not be derecognized.

De-recognition of the University by the State Government

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under subsection (1), the State Government is satisfied that a prima-facie case of mismanagement or violation of the provisions of this Act in the functioning of the University is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary.

(3) For the purpose of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into the allegations of violation of the provisions of this Act.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Act have all the powers of Civil Court under the code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office
- (d) receiving evidence on affidavits;
- (e) any other matter which may be prescribed.

(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act, it shall direct the University to make necessary improvement and suggest for proper implementation of the provision of this Act.

(6) If it is observed that the University is violating the Act continuously for three times the State Government may derecognize the University with prior approval of the University Grants Commission.

(7) During the period of the management of the University under sub-section (6), the State Government may utilize the permanent endowment fund, the general funds or the development fund for the purpose of the Management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose of the assets or the properties of the University to meet the said expenses.

(8) Every notification under sub-section (6), shall be laid before both houses of the State Legislature before implementation.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

51. The State Government may issue such directions time to time to University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University.

Status of Assets/Liabilities on Dissolution/de-recognition

52. All assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund and also the liabilities of the University will belong to the Trust in case of dissolution of the University under any clause mentioned herein above in the Act.

Power to remove difficulties

53. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging private sector to participate in the field of higher education, it has been decided to establish and incorporate a teaching University at Gautam Buddha Nagar in Uttar Pradesh by the name of Noida International University sponsored by Maruti Educational Trust, Aligarh registered under the Indian Trust Act, 1882 (Act no. 2 of 1882), so as to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of innovations leading to proper structuring of teaching and learning and integral development of personality.

The Noida International University Uttar Pradesh Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,  
K.K. SHARMA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०प०-ए०पी० 641 राजपत्र-2010-(1317)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०प०-ए०पी० 104 सा० विद्या०-2010-(1318)-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।